

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विधानमंडल (तत्कालीन) में प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया था और भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार अप्रैल 2018 में राज्यपाल को भेजा गया था। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (जून 1994) के निर्णयानुसार, जहां कहीं एक वर्ष से अधिक के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हो, वहां राज्य से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए यह प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति को भेजा जा रहा है।

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अन्तर्गत जम्मू एवं कश्मीर राज्य के पुनर्गठन होने पर यह प्रतिवेदन परवर्ती संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के उपराज्यपालों को भेजा जा रहा है।

इस प्रतिवेदन में दो भाग हैं।

#### **भाग-क: राजस्व क्षेत्र**

इस भाग में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत की गई प्रमुख राजस्व अर्जित करने वाले विभागों की प्राप्तियाँ और व्यय की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

#### **भाग-ख: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**

इस भाग में मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों की नमूना लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा सरकारी कंपनियों (कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मानी जाने वाली सरकारी कंपनियों सहित) के लेखाओं की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 और कंपनी अधिनियम 2013 की धाराओं 139 और 143 के प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधान के अंतर्गत की जाती है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के अंतर्गत सरकार द्वारा विधानमंडल में यह लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामलों में वे मामले शामिल हैं जो वर्ष 2016-17 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आये, साथ ही वे मामले भी, जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आये, किन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे। वर्ष 2016-17 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी, जहां आवश्यक हो, शामिल किये गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

